श्री महेन्द्र सिंह लाठर

लिए कोई बाथ रूम नहीं है उनको खुले में नहाना पड़ता है। ऐसे नर्क में रह रही लड़कियों में से एक लड़की ने मरने की कोशिश की। यह मामला इतना गंभीर है लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है जिसके बारे में टाइम्स आफ इण्डिया में निकला है। यह बड़ी शर्मनाक बात है।

महोदय, यहां पर औरतों के खिलाफ अत्याचारों के बारे में बार-बार मामले उठाए जा रहे हैं लेकिन कोई कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। वहां पर एक चौकीदार है जो आदमी है उसको वहां रात को रहने की इजाजत होती है लकिन कोई लेडी वहां पर नहीं रह सकती है। ...

उपसभापति: अब आप इतना लंबा भाषण मत करिए आप बैठ जाइए। ...

श्री महेन्द्र सिंह लाठर: महोदया, मेरी मांग है कि इस मामले की जांच कराएं और उसकी रिपोर्ट लेकर सदन को सरकार बताए।

RE. ATROCITIES ON INDIAN WOMEN EMPLOYEES IN KUWAIT

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं आपके जरिए सरकार का ध्यान कुवैत में भारतीय महिला कर्मचारियों पर होने वाले अत्याचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर नर्सिंग होम्स और विभिन्न अस्पतालों में हजारों औरतों के साथ जो भारतीय मूल की हैं, उनके साथ रेप किया जा रहा उनका फिजिकल ऐसॉल्ट किया जा रहा है हैं। उनको लोहे की छड़ों से मारा-पीटा जा रहा है। उनका सामान छीन लिया गया है और वह जान बचाकर भाग कर एंबेसीज में आ गई हैं हजारों की तादाद में औरतें सड़कों पर पड़ी हुई है, ऐंबेसी में छिपी हुई हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही है उनकी हिफाजत के लिए। कुवैत में जो हमारे ऐंबेसेडर हैं वह उनको अनदेखी कर रहे हैं। जिन औरतों के साथ रेप हुआ जिनको मारा गया, जिनको चोट पहुंचाई गई है, उनकी थाने में रिपोर्ट की जाती है। उनके द्वारा दरख्वास्त की जाती है लेकिन कुवत सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है। उनका जो पैसा रुपया था वह भी उन्होंने छीन लिया है। वह कहीं आ जा नहीं सकती हैं। हमारी ऐंबेसी में जो औरतें पड़ी हुई हैं हमारे ऐंबेसेडर कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर बयान दे।और जो वहां हजारों की तादाद में महिलायें पड़ी हुई हैं, उनके आने का इंतजाम किया जाए और हमारे यहां जो कुवैत का राजदूत है उसे बुला कर सरकार तुरंत बात करें।

यह बड़ा गंभीर मसला है और इस सरकार को बड़ी गंभीरता से इसको लेना चाहिए और जो उनके साथ सुलूक किया गया है उनका माल गया है उनकी बेइज्जती हुई है उसका मुआवजा भी उनको देना चाहिए। ... (**व्यवधान**)

उपसभापति: यह बात पूरी तो हो जाए। यह मामला पूरा हो जाए।

चौधरी हरि सिंह: नौकरी के लिए उनको वहां नहीं भेजना चाहिए।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, I want to associate myself with this. There have been a lot of stories published in my State also. I have already put a question to the External Affairs Ministry. It is not proper, Madam. Madam, I have requested the Government to use our diplomatic channels to see that our people are protected because there is panic not only in Kuwait but there is panic in our country also. The Government should respond to that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Anything else? Yes.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं। ... (**व्यवधान**)

उपसभापति: नहीं, बस सपोर्ट हो गया। अब आगे जाने दें।

श्री राम नरेश यादव: नहीं, सरकार इस पर एक वक्तव्य... (**व्यवधान**)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Madam, I also want one minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Jacob Saheb wants to raise something.

RE. REVIEW OF 15 POINT PROGRAMME FOR MINORITIES BY THE CABINET COMMITTEE

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 15–नुकाती जो अक्कलियतों की फलाह और बहबूदी के लिए मिसेज़ इन्दिरा गांधी ने शुरू किया था, उस प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) अबरार साहब मैं एक मिनट लूंगा–कि पिछली तमाम सरकारों ने, खास तौर पर मि. राजीव गांधी के दौर में और मि. वी. पी. सिंह के दौर में बाकायदा उसको रेव्यु कैबिनेट कमेटी हर दो-तीन महीने के अंदर किया करती थीं।

मेरे इल्म में आया है कि पिछले एक साल से जो यह सरकार आई है, उसने कोई कैबिनेट कमेटी की मीटिंग 15–प्वाइंट प्रोग्राम को रेव्यु करने के लिए अभी तक नहीं बुलाई है। अगर यह सच है तो यह बहुत ही अफसोसनाक है। अक्कलियतों का जो हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर वह किसी से ढका और छिपा नहीं है। तालीम के अंदर, माशी नाबराबरी के अंदर उनके साथ जो कुछ भी सुलूक हो रहा है मैं उसका बयान नहीं करना चाहता हूं। पूरा हाऊस और पूरा मुल्क उससे वाकिफ है।

तालीम के ऊपर तवज्जह नहीं दी जा रही है। सुबह से शाम तक सरकार बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि के लिए तो लगी रहती है, लेकिन अक्कलियतों के जो बुनियादी मसायल है, उनके ऊपर कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि पिछले एक साल से यह सरकार मौजद है और इसने कैबिनेट कमेटी की कोई मीटिंग माइनार्टीज़ के सिलसिले में जो 15–प्वाइंट प्रोग्राम को रेव्यु करने के लिए बुलाई जाती थी, ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई।

इसका मतलब यह है कि सरकार को अक्कलियतों के फलाह और बहबूदी से कुछ लेना-देना नहीं है। वह अक्कलियतों के ज़ज्बाती मसायल को उभार करके सिर्फ उनके अंदर पापुलर होना चाहती थी।

इन्होंने पिछले दिनों एक बिल पास किया, और 1947 के सिलसिले में जो इबादतगाहों का बिल पास किया था... (व्यवधान)

उपसभापति : प्लीज़, बैठिये।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : ...और मैडम, उसके बाद इन्होंने अक्कलियत कमीशन को थोड़ा बहुत कानूनी दर्जा देने की कोशिश की।

उपसभापति : अच्छा, अब आप बैठिये।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : लेकिन वह अक्कलियत कमीशन किस काम का है जब 15–नुकाती प्रोग्राम के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। मैडम, यह बहुत ही अफसोसनाक बात है। ..(व्यवधान)

उपसभापति : अच्छा, अब आप बैठिये।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम, यह बहुत ही अहम बात है, मैं सरकार से दर्खास्त करूंगा कि वह हर महीने 15–नुकाती प्रोग्राम को रेव्यु करने के लिए कैबिनेट कमेटी बुलायें और सदन को आगाह करें कि कौन-कौन सी स्टेट माइनार्टीज़ के सिलसिले में 15–प्वाइंट प्रोग्राम को लागू कर रही हैं और कौन सी लागू नहीं कर रही हैं।